ऐक्वीजीशन की समस्या का समाधान कैसे होगा, उस पर हम लोगों ने विचार कर लिया है, निर्णय कर लिया है।

†**श्री मोहम्मद सलीम:** सर, प्रश्न के उत्तर का विस्तार किया गया, इस संबंध में मैं कोई स्पैसिफिक आंसर नहीं चाह रहा हूं लेकिन यह जो आप कॉड्रीलैट्रल और नॉर्थ-ईस्ट कॉरीडोर की और साउथ-वैस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें जो पुराने शहर थे, उसमें कुछ हैरीटेज सिटीज हैं, कुछ हैरीटेज साइट्स हैं। जब यह योजना बनायी गयी तो इसमें ऐक्सपर्ट्स, का ओपीनियन नहीं लिया गया—ऊपर से सिर्फ दिमाग में आया और अनाउंस कर दिया गया। इसमें हमारी जो हैरीटेज साइट्स हैं—दोनों तरफ से—एक तो पुराने शहारों की कनैक्टीविटी का मामला है और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट पिल्लर्स हैं, टाउनशिप्स हैं, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचे, इस बारे में आप क्या प्रावधान कर रहे हैं?

श्री राजनाथ सिंह: माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि बहुत सोच-विचार कर और कंसल्टेंट्स की राय लेने के बाद ही टास्क फोर्स ने इस प्रोजेक्ट के संबंध में अंतिम निर्णय किया है इसलिए यह कहा जाना कि हमने कोई ऐसा फैसला कर लिया है, यह उचित नहीं है लेकिन इस परियोजना को तैयार करते समय यह विचार किया गया था कि जिन मार्गों पर ट्रैफिक डेनसिटी अधिक हो, जहां से आम लोगों का आवागमन ज्यादा होता हो, उसी को लिया जाए। इस आधार पर यह किया गया था और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे कि इसके रीएलाइनमेंट के बारे में विचार किया जाए तो मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि फिलहाल यह संभव नहीं है क्योंकि परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

Cellular Telecom Services

*163. SHRI NILOTPAL BASU:‡
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the TRAI has referred to cellular telecom services as a premium service and not a utility service in its documents;

(b) if so, the response of Government in accepting this assessment; and

(c) if such a service is indeed a premium service, the reasons for foregoing the deemed payment from private cellular telecoms and going ahead with migration package and claiming this as 'public good'?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) A statment is laid on the Table of the House.

†Transliteration of the Speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.

‡ The question was actually asked on the floor of the House by Shri Nilotpal Basu.

Statement

(a) and (b) While the cellular service has been referred by TRAI in some of their documents as a premium service, it is at the same time generally perceived to be of considerable utility to the users to this service.

(c) While approving New Telecom Policy— 1999 (NTP-99), the government considered, *inter alia*, that it is in public interest for the New Telecom Policy to be uniformaly applicable throughout the country. Therefore, the policy regarding migration of the existing licensees of Basic and Cellular Services to the NTP-99 regime of revenue sharing arrangement was formulated and approved. This would ensure growth of telecom sector by bringing in multipoly, better accessability and improved/ cost effective service to customers and is important for achieving the objectives of New Telecom Policy.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, the difficulty with the Government is, when we expect an answer from the Government, there is no answer. Sometimes, the Government gives answers to questions which we have not asked. I would like to refer to part (a) of my question. The question was, "Whether it is a fact that the TRAI has referred to cellular telecom services as a premium service and not a utility service in its documents." The reply is, "While the cellular service has been referred by TRAI in some of their documents as premium service, it is, at the same time, generally perceived to be of considerable utility to the users of this service. I think the statement is quite self-explanatory. On the one hand, the Government is replying to questions which have not been asked, and on the other, the Government is not categorical in terms of giving replies to very specific questions. Now this is budget time and we are hearing a lot of concern being expressed about subsidies. I would like to put a specific question to the Minister of Communications. On 6th July, 1999 the Cabinet took a decision approving a package for the migration of cellular operators. Is it not a fact that the Ministry of Finance had given a specific note to the Ministry of Communications saying that there was a specific need for studying the financial status of each of these companies which were claiming that they were in distress and thereafter the benefit should accrue to them? I would like to know whether such a study was made. I would also like to know whether such study reflected this basic fact that cellular service is not a utility service but a premium service.

श्री राम विलास पासवान: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है और जो हमने जवाब दिया है, हमको ऐसा कहीं नहीं लगता है कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन है। हिंदी का जवाब भी मेरे पास

उपलब्ध है और अंग्रेजी का भी । मै हिंदी में बोल रहा था तो सोच रहा था कि ये अंग्रेजी में प्रश्न पूछ रहे हैं...। एक प्रश्न आपने किया है कि

"Whehter it is a fact that the TRAI has referred to cellular telecom services as a premium service".

तो हमने इसका जवाब दिया है कि ट्राई ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट में "While the cellular service has been referred by TRAI in some of their documents as a premium service" तो हमने कहा कि हां, प्रीमियम सर्विसेज के संबंध में उस डाक्यूमेंट में ... उसमें दो डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है टेली कम्युनिकेशन्स इंटरकनेक्शन्स चार्जेज़ एंड रिवेन्यू शेयरिंग अमेंडमेंट रेग्युलेशन्स, 1999 और दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन टैरिफएक्ट, फिफ्थ अमेंडमेंट ऑर्डर, 1999 लेकिन हमने उसके साथ ही यह भी कहा है कि "It is, at the same time, generally perceived to be of considerable utility to the users of this service."

किसी समय में एक चीज़ हो सकती हैं कि वह पर्टिकुलर्ली एक एफ्लुएंट क्लास के लिए हो, बड़े लोगों के लिए हो लेकिन धीरे-धीरे वह आम लोगों की युटिलीटी की सर्विस बन जाती है। एक समय में सेल्युलर सर्विस बड़े-बड़े लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती थी लेकिन आज मिडिल क्लास के लोगों ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे ऐसा समय भी आएगा जब इसकी कीमत और घट जाएगी और सेल्युलर टेलीफोन हर गांव में उपलब्ध हो जाएगा।

जब यह आम लोगों के लिए हो जाएगा तब यह पब्लिक यूटिलिटी में आएगा। इसमें कंट्राडिक्शन कहां है दूसरी बात आपने फांइनेंस मिनिस्ट्री के संबंध में कही है तो इसमें उसका कोई संबंध ही नहीं है। आपने मेन प्रश्न पूछा है जिसके दो भाग हैं। एक भाग में यह पूछा है कि यह सर्विस पब्लिक यूटिलिटी के लिए है या नहीं हैं और दूसरे भाग में यह पूछा है कि आपने उनको छूट क्यों दी है? इस संबंध में यदि आपको कोई जानकारी लेनी हो तो मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

SHRI NILOTPAL BASU: He has clearly avoided my question. My supplementary arises from this question. If is a utility service, then the approach will be one kind; and if it is a premium service, then the approach will be different. And, I maintain that it is a premium service.

आप हाउस को मिसलीड न करें और यह बताने का कष्ट करें कि आज देश के अंदर जो बेसिक सर्विसेज हैं उनके तहत आपके कितने टेलीफोन कनैक्शन्स हैं, कितनी प्रीमिमय सर्विसेज हैं। और कितनी सैल्यूलर सर्विसेज है? सदन को गुमराह मत करिए।

श्री रामविलास पासवान: ऐसा नहीं है, मेरे पास डिटेल्स है। अब पूरे देश में सैल्यूलर मोबाइल सर्विसेज के पन्द्रह लाख कनैक्शन्स हैं।

श्री नीलोप्तल बसु: पन्द्रह लाख कनैक्शन्स हैं, आप यह बोल रहे हैं?

श्री रामविलास पासवान: जी,

श्री नीलोत्पल बसु: बेसिक कनैक्शन कितने हैं? ...(व्यवधान)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, like a cellular phone without a connection, they are talking to each other.

श्री रामविलास पासवान: इस देश में बेसिक कनैक्शन, 2,49,78,000 है।

SHRI NILOTPAL BASU: So, it is apparent what has happened with this. Now, finally, in reply to part (c) of the question, the Government has admitted that for uniformly applying the package, one system of revenue-sharing package has been approved. Now, this was approved by the Government on the 6th of July. Subsequently, some of the operators have not fulfilled the conditions of the package. For instance, in the case of one of the companies, Messrs Koshika Telecom, its case came up before the Government, and the Attorney-General's opinion was sought. In October, the Attorney-General said that their case for restoring the connection has to be there. This was very categorically stated by the Attorney-General. If the package was meant for uniform application, why was it not implemented? And, why is it that in February, the same Attorney-General gives the opinion that though these fellows have not complied with the conditions of the package, their connection should be restored?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: What can we say about the Attorney-General's opinion?

श्री रामविलास पासवान: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उससे मैं यह नहीं समझ पाया के वे क्या पूछना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वयं कन्फ्यूज हैं क्योंकि इनका मेन थ्रस्ट है ... और क्वेश्चन मेरे पास है, इन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि यदि ऐसी सेवा वास्तव में प्रमुख सेवा है, प्रीमियम सर्विस है तो निजी सैल्युलर दूर संचार कम्पनी की ओर से बकाया भुगतान छोड़ देने और माइग्रेशन पैकेज को जारी रखने और इसे लोक कल्याण के रूप में दावा करने का क्या कारण है? आपका मेन परपज है कि उसको छूट क्यों दी गई और इस संबंध में मैंने यह कहा है कि उनको छूट देने का सबसे बड़ा कारण था कि हम चाहते थे कि पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी लागू हो। दूसरे हम यह चाहते थे कि उनको भी फ्री-कम्पीटिशन में लाया जाए तथा डयूओपॉली से मल्टीपॉली में कन्वर्ट किया जाए। यह तभी होता जबकि इनको नए पैकेज माइग्रेशन पैकेज में लाया जाए। तीसरा यह था कि उनको नोशनल इफेक्टिव डेट छ: महीने की नहीं बढ़ाई गई और चौथा सबसे बड़ा कारण था कि चौथे साल के बाद जिनको लाइसेंस दिया

गया था वे इस पोजिशन में नहीं थे कि वे पैसा दे सकें और यदि उसका हमारे पास ...(व्यवधान)... इस तरीके से ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Let him answer completely.

SHRI NILOTPAL BASU: He is not answering the question. That is the whole trouble. He is evading the question. I have asked about the financial status. He is not revealing this...

श्री रामविलास पासवान: सर, मैं जवाब में कितना स्पेसिफिक हूं, ...(व्यवधान)...

You go through the record and if any point is irrelevant...(*Interruptions*) I do not know what he wants.

आप क्या चाहते हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि क्यों प्राइवेट सेलुलर वाले लोगों पर बोझ पड़ रहा था, क्यों दूसरी माइग्रेशन पोलिसी लाई गई। इसका मैं एक एग्जेम्पल देना चाहता हूं। चार मेट्रोपालिटन सिटीज है। मुम्बई में प्रतिवर्ष के हिसाब से लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ रही थी पहले साल में 3 करोड़ रुपये, दूसरे साल में 6 करोड़ तीसरे में 12 करोड़ , चौथे साल में 108 करोड़ रुपये। जो नया था 6,023 रुपये, प्रति सबसकाइबर के हिसाब से, उसके मुताबिक उनके ऊपर 108 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा था। दिल्ली में लाईसेंसिंग फीस पहले साल में 2 करोड़, दूसरे साल में 4 करोड़ तीसरे साल में 8 करोड़ और चौथे साल में बढ़कर 80 करोड़ हो गई थी। इसी तरह से कलकत्ता में पहले साल में 1.5 करोड़ रुपये, दूसरे साल में 3 करोड़ रुपये, तीसरे साल मे 6 करोड़ रुपये और चौथे साल में 24 करोड़ रुपये हो गई थी। इसी तरह चेन्नई में पहले साल में 1 करोड़ रुपये लाइसेंसिंग फीस थी, दूसरे साल में 2 करोड़ तीसरे साल में 4 करोड़ और चौथे साल 20 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार चौथे साल के बाद जो एमाउण्ट बढ़ गया था उससे वे उस पोजीशन में नहीं थे कि उसे दे सकते।

तीन कारण मैंने बतलाए थे। एक कारण था यूनिफोर्मिटी होनी चाहिए, दूसरा कारण डियो पोलिसी से मल्टी पोलिसी में करना क्योंकि कम्पीटीशन में लाना था। तीसरा, हर गांव में टेलीफोन की सुविधा प्रदान करना था और चौथा, उनके ऊपर जो बोझ पड़ रहा था, इस बोझ के कारण जो इंडस्ट्री मर रही थीं और लोगों की सुविधाएं समाप्त हो रही थीं उन सुविधाओं को देने के लिए हमने यह पैकेज लागू किया और इस संबंध में ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसी सदन में इस पर चर्चा कराई, तीन घण्टे चर्चा चली। सिब्बल साहब यहां बैठे हुए है, विस्तार से चर्चा हुई। उस दिन उनको पूरा सैटिसफाइड कर दिया गया था, यदि उससे भी मेम्बर सैटिसफाइड नहीं हैं तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते।

SHRI NILOTPAL BASU: But he has not answered my question. All these companies which they are mentioning that they are in distress, have made huge killings in the share markets. How has the Attorney-General changed his opinion? They are looting the public exchequer.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Chairman, Sir, the reply to the question says "This would ensure growth of telecom sector by bringing in multipoly, better accessibility and improved/cost effective service...". Sir, for cost-effective service I feel that the cost of the service providers itself has its own bearing. The level-playing factor has got its own place in this. Here, there are two players. One is the Department of Telecom and the other is the cellular operator. The Department of Telecom has got 14 times more than the cellular telephone numbers. Therefore, it has got its own important place. Sir, what I want to know is, in case we make a call from a basic telephone to a cellular telephone, the Department of Telecom has to shell out some money to the cellular operators. If it is from cellular to basic, the cellular operators have to shell out some money to the Department of Telecom. But the percentage is not equal. In case a person makes a call from a basic telephone to a cellular telephone, he has to pay more. The Department of Telecom has to pay more to the cellular operators than otherwise. Therefore, I want to know that when it is so, then the Department of Telecom will be affected more than the cellular operators. I would like to know whether it is a fact. If it is so, how is the Government going to rectify this error and make the Department of Telecom work more profitably and ensure that there is a level playing field for the DoT vis-a-vis the cellular operators.

श्री रामविलास पासवान: सभापति महोदय, इसके लिए जो ट्राई है, ट्राई का जो मामला है उसके अंडर में टैरिफ का मामला आता है। ट्राई को पूर्ण अधिकार है उसे देखने का और ट्राई का जो भी आर्डर होता है उसे हम मानते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खान: सभापति महोदय, मंत्री जी ने सेलुलर वालों के बारे में कहा है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, he has not replied to my question. I have asked whether the level-playing field is going to be affected. The Department of Telecom is going to pay more money to the cellular operators in case the call goes from basic to cellular. On the other hand, the cellular operators are not going to pay the same percentage as the Department of Telecom is going to pay to the cellular operators. By this, the Department of Telecom will be affected more than the cellular operators. Therefore, I want to know whether there will be an equal percentage. Whatever percentage the

cellular operator is going to pay to the DOT, the DOT also should pay only that much. This was my question, but I did not get the reply from him. Because of this, the Department of Telecommunications will be affected more, as compared to the cellular operators. Therefore, I want to know whether there will be a parity in payments that are to be made by DoT to the cellular operator and vice-versa. I did not get reply from the hon. Minister.

श्री रामविलास पासवान: मैंने बतला दिया कि पहले 'ट्राई' थी, अब 'ट्राई' है और एक ट्रिब्यूनल है। इनका गठन किया गया है। एक का काम रिक्मेंडेटरी है और टैरिफ के मामले में उनको पूरा का पूरा अधिकार है। यदि लाइसेंसी और लाइसेंसर के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ट्रिब्यूनल को पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। उसको इतना अधिकार दिया गया है कि उसके बाद समय की उसमें बरबादी नहीं हो। हाई कोर्ट की ही नहीं बल्कि उसको सीधे सुप्रीम कार्ट में अपील का अधिकार दिया गया है। इसलिए ये दोनों मामले 'ट्राई' के अधीन आएंगे और एक जो एडजुडिकेशन है, उसका जो मामला है, वह ट्रिब्यूनल के अधीन आ जाएगा। इसलिए जो समान स्तर पर दोनों को समानता देने की बात है या किसी का किसी के प्रति कोई शोषण नहीं हो, इसको पूरी की पूरी दोनों बाडीज ध्यान में रखेंगी और सरकार के लिए वह बाइंडिंग होता है।

†**श्री मोहम्मद आज़म खान:** मंत्री जी ने अभी सेल्यूलर टेलीफोन्स के बारे में यूनिफार्मिटी की बात की है। पूरे देश में यूनिफार्मिटी होनी चाहिए। कहने के लिए यह बात अच्छी है, सुनने में भी अच्छी लगती है। पिछले दिनों अखबारों में आया कि इनकमिंग काल्स का पैसा खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में इनकमिंग काल्स का एक रुपया है और दिल्ली से बाहर दूसरे प्रदेशों में ज्यादा है, कहीं ज्यादा है-चार गुना, पांच गुना है। तो क्या इस सिलसिले में भी मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे कि जब हम यूनिफार्मिटी की बात करें तो लेन और देन दोनों के बारे में यूनिफार्मिटी हो। इनकमिंग काल्स और आउटगोइंग काल्स का पैसा पूरे देश में, दूसरे प्रदेशों में, केन्द्र में एक ही होना चाहिए और इस फर्क को जो बहुत ज्यादा है-दिल्ली में एक रुपया इनकमिंग काल्स का है और दूसरे प्रदेशों में चार रुपए कुछ पैसे है-इसको खत्म करने के लिए कुछ आश्वासन देंगे?

श्री रामविलास पासवान: सर इस संबंध में हम कोई आश्वासन नहीं देंगे। इसलिए आश्वासन नहीं देंगे चूंकि हमारे ज्योरिसडिक्सन का यह मामला नहीं है, चूंकि बार-बार डिपार्टमेंट आफ टेलीफोन के ऊपर यह चार्ज लगता रहा है कि हम फ्री कंपटीशन नहीं होने देते हैं। इसलिए यह मामला 'ट्राई' का है और 'ट्राई' का जो रिक्मेंडेशन होता है उस 'ट्राई' के रिक्मेंडेशन के मुताबिक हम एक्ट करते हैं और 'ट्राई' ही तय करता है कि कहां कितना टैरिफ होना चाहिए, रूरल में कितना होना चाहिए, अरबन में कितना होना चाहिए। यह पूरा का पूरा 'ट्राई' के ज्योरिसडिक्शन का मामला है।

---

†Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the debate.

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, सेल्यूलर फोन का उपयोग करने वाले मध्यमवर्गीय लोग भी हैं। मंत्री जी ने भी कहा। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में तीन-चार बातें आई हैं। बड़ी संख्या में सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों में सेल्युलर फोन का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। इसका दुरुपयोग भी होता है लिहाजा बिल अदायगी कार्यालय करता है, सरकार करती है, खर्च बढ़ रहा है। सेल्युलर फोन वाले कार इसको आन करके चलाते हैं। दुर्घटनाओं में अनेकों मर गए और मरने की संभावनाएं बढ़ रहीं हैं। तीसरी चीज ...(व्यवधान) जो कह रहा हूं परसनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं और अब पूछ रहा हूं तीसरी बात कि इसका खर्च इतना है कि जिसकी नैतिक संसाधनों से पूर्ति नहीं होती है। तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जनउपयोगिता के साथ-साथ जो यह भ्रष्टाचार, फिजूल का खर्च और जान को खतरा बढ़ रहा है क्या इसकी भी समीक्षा मंत्री जी करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: सर, एक तो मैं पहली बात कहूंगा कि माननीय सदस्य यह मत कहें कि परसनल एक्सपीरियंस के आधार पर है ...(व्यवधान) दूसरी बात है, जहां तक मैं समझता हूं कोई प्रश्न नहीं है यह इनका ओपीनियन है, सजेश्चन है जो हमारी समीक्षा करने के बाहर है।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I would like to know this from the hon. Minister, because we had a detailed discussion on this earlier in the House. I also want to inform the House that there are three categories of telephone operators. One are those who provide basic services. The second category are the metro operators and the third are the non-metro operators. It is the non-metro operators who had defaulted on the license agreement and could not pay their fees and the Government came out with the package to help the non-metro operators. As far as the basic service operators are concerned and as far as the metro operators are concerned, they had at no stage defaulted on their license fee. There was no litigation pending anywhere. They were to pay their licence fee in a gradual fashion. In the earlier years, they were to pay less; in the later years, they were to pay more fee. When the time came for paying the large amount of fee, by that time, the Government decided to graduate them from the licence fee regime to the package regime. That is how these people are benefited. Now, could the Minister please inform the House as to what is the extent of licence fee amount that has been lost by the Government in this package from the metro operators and from the basic service operators, and also having extended this period for 20 years, what is the revenue that the Government intends or hopes to gain? Then, could the Minister inform the House as to what the deficit would be? If this exercise has not been done, could the Minister do this exercise and inform the House?

श्री राम विलास पासवान: सर, कितने लॉस का अनुमान है वह तो मैं इन्फार्म कर दूंगा, क्योंकि उसमें कहीं कुछ हजार करोड़ आता है, कहीं कुछ हजार करोड़ आता है। लेकिन ये सारी की सारी काल्पनिक चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब कहीं एक पैसा आ ही नहीं रहा था, आज तो कम से कम हमने 35 परसेंट उनसे ले लिया और सारा का सारा एग्रीमेंट उन्होंने कर दिया ...**(व्यवधान)**

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, a sum of Rs. 3,000 crores has been lost ...(*Interruptions*)... The Minister should tell the truth to the House. ...(*Interruption*)...

SHRI KAPIL SIBAL: Would the Minister kindly yield for a minute? ...(*Interruption*)...

नहीं, सवाल यह है .....**(व्यवधान)** एक मिनट, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पैसा आ नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने पूछा कि इन लोगों ने तो कभी डिफाल्ट ही नहीं किया, आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा आ नहीं रहा था?

जब डिफाल्ट ही नहीं हुआ, बेसिक अपारेटर्स ने कभी डिफाल्ट नहीं किया है और मेट्रो आपरेटर्स ने डिफाल्ट नहीं किया तो आप कैसे कह रहे हैं कि पैसा आ नहीं रहा था? तो इनमें से आप एक भी आपरेटर का नाम बताइये जिसने पैसा नहीं दिया या पैसा आ नहीं रहा था?

श्री राम विलास पासवान: सभापति जी, मैंने उस दिन भी कहा था और मैं कभी छिपाता नहीं हूं.....**(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: आप एक भी नाम लीजिए।

श्री राम विलास पासवान: जो भी आपने प्रश्न उठाया है कि किनके पास में कितना पैसा बकाया था, किसने पैसा जमा नहीं किया, कितना अनुमानित इसमें लॉस होने की संभावना थी, मैं यह पूरा का पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर रख दूंगा।.....**(व्यवधान)**

SHRI MD. SALIM: Sir, please protect us....(*Interruptions*)....

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, the Minister is misleading the House....(*Interruptions*)...

श्री कपिल सिब्बल: क्या एक भी ऐसा आपरेटर है, आप एक भी नाम दे दीजिए?

श्री राम विलास पासवान: सर, जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पालिसी के ऊपर पूछा गया है। ... **(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: यही तो पालिसी का क्वेश्चन है। आपने कहा कि पैसा नहीं आ रहा था तो आप एक भी बेसिक आपरेटर का नाम दीजिए जिसका पैसा नहीं आया? ...**(व्यवधान)**

ये हाउस में स्टेटमेंट करते हैं कि पैसा नहीं आ रहा था, तो उसका कोई तो आधार होना चाहिए? ...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, when the call is through, nobody has got a right to disrupt or interrupt that call. When the Minister was responding, the Member is frequently raising one issue after another, and making a running commentary. ....(*Interruptions*)....

SHRI KAPIL SIBAL: No, no. He is not answering the question. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Cellular phone is a very costly affair. The hon. Member must hear the Minister first. ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: He has made a statement which is factually incorrect. ...(*Interruptions*)... That statement is factually incorrect. ...(*Interruptions*)... He should give the name of one basic operator who has defaulted. ...(*Interruptions*)...

श्री राम विलास पासवान: सर, मैंने माननीय सदस्यों को कहा कि पालिसी जो है वह रंदा के समान चलती है, बर्मी के समान नहीं चलती है। जब पूरे देश को हमने कहा कि हम डयो पोली से ले करके, दो व्यक्ति से ले करके, हम मल्टी पोली में ले जाना चाहते हैं तो मैंने चार कारण बतलाए हैं, जो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मैंने कहा कि पूरे देश में हम एक पालिसी लागू करना चाहते थे, दूसरा हम मेट्रो में भी मल्टी पोली को लाना चाहते थे। ...(**व्यवधान**)

SHRI JANARDHANA POOJARY: He is evading the question. ...(*Interruptions*)...

†**श्री मोहम्मद सलीम:** यह अच्छे मंत्री हैं। ...(**व्यवधान**) पुराने कारनामें हैं, लेकिन ऐसे दलदल में फंस गए कि निकलना मुश्किल हो गया। ...(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान: सर, मैंने शुरू में ही कहा ...(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु: दूसरा कोई कर रहा है ...(**व्यवधान**) आप क्यों फालतू जिम्मेदारी ले रहे हैं? ...(**व्यवधान**)

†**श्री मोहम्मद सलीम:** नहीं तो मंत्री बदल जायेंगे ...(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु: कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप फालतू क्यों इसको भुगत रहे हैं। ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

---

†Transliteration of the Speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.